डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन/डिस्पेच दिनांक 1 अगस्त, 2019

| वर्ष 63 | अंक 05 | भोपाल | 1 अगस्त, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

गुणवत्ता बढ़ाकर को-ऑपरेटिव क्षेत्र कार्पोरेट को दें चुनौती : श्री भूपेश बघेल

'मध्य क्षेत्र के राज्यों में सहकारी आंदोलन के समक्ष अवसर और चुनौतियां' विषय पर सम्मेलन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यहां 'मध्य क्षेत्र के राज्यों में सहकारी आंदोलन के समक्ष अवसर और चुनौतियां' विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता ने भारत में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में यह जरूरी है कि कोऑपरेटिव क्षेत्र अब अपनी गुणवत्ता बढ़ाने पर पूरा जोर दे और कार्पोरेट को चुनौती दे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नया रायपुर में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की।

यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया था। सहकारिता से जुडे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह भी जरूरी है कि सहकारिता के कार्यों के प्रति व्यवसायिक दृष्टि अपनाई जाए और क्वालिटी पर सर्वाधिक जोर दिया जाए। अगर गुणवत्ता पर जोर नहीं दिया गया तो सहकारिता मार्केट में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा और सरकार पर निर्भर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य सहकारिता को प्रोत्साहित करना है पंगु बनाना नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी जरूरी है कि सहकारिता से जुड़े उत्पाद और सेवाएं हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना के माध्यम से हम उन चुनौतियों और समस्याओं का सामना कर सकते है। जो आज केवल देश की नहीं बल्कि दुनिया की भी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अब ओनहारी और उतेरा की फसल करीब–करीब बंद सी हो गई है। इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए फसलों को पशुओं के चराई से बचाने, वर्मी कम्पोस्ट को बढावा देने और जल संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं द्वारा नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना में भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त किए जाने पर उनका स्वागत किया और कहा कि सबके द्वारा मिलकर कार्य किए जाने से छत्तीसगढ़ देश भर के लिए रोल मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा भारत सरकार ने तीन वर्षों तक लगातार वर्मी एवं कम्पोस्ट खाद से फसल लेने पर उसे जैविक उत्पाद घोषित करनी की घोषणा की लेकिन इस अवधि को बढा कर अब पांच वर्ष कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार पुनः विचार करते हुए फिर से जैविक उत्पाद घोषित करने की समय–सीमा घटा कर पूर्व के अनुसार तीन वर्ष रखने की मांग की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि कृषि, कृषक और सहकारिता एक दूसरे के पूरक है। इनमें बेहतर सामंजस्य की जरूरत है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जिसमें किसानों का लगभग साढ़े ग्याहर हजार रूपये की राशि का कृषि ऋण माफ किया है। नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश को प्रकृति की रक्षा, जल संसाधन को बचाने, पशुधन को बढ़ाने और जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में देश को अच्छी राह दिखाई है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रपाल यादव ने बताया कि देश में अनेक सहकारी संस्थाएं अदभुत कार्य कर रही हैं। किसानों की खुशहाली और मजबूती के लिए सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सहकारी बैंकों में समिति कर्मियों से भरे जायेंगे 60% पद : डॉ. गोविन्द सिंह

प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने का आव्हान

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि सहकारी बैंकों में 60 प्रतिशत पद सहकारी समिति कर्मियों से भरे जायेंगे। भर्ती में अनुभव का लाभ दिया जायेगा। पदोन्नति के अवसर निर्मित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अब सहकारी समिति कर्मियों के लिये शैक्षणिक योग्यता स्नातक आवश्यक नहीं होगी, हायर सेकेण्डरी योग्यता ही पर्याप्त होगी। श्री सिंह यहाँ मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रादेशिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।

डॉ. गोविन्द सिंह ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये सहकारिता कर्मियों का आव्हान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हितों का संरक्षण करेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों में प्रत्येक स्तर पर कैडर बनाये जायेंगे। समितियों से हटाये गये कर्मियों को वापस रखने की कार्यवाही की जायेगी।

सहकारिता मंत्री ने सहकारी कर्मियों से जय किसान फसल ऋण माफी योजना से अधिकाधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सहकारी कर्मियों पर दर्ज एफआईआर प्रकरणों की जाँच की जायेगी। दोषी कर्मियों पर कार्यवाही होगी और निर्दोष कर्मियों के प्रकरण वापस लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले सहकारी कर्मियों को सहकारी बैंकों में सीधे नियुक्ति दिये जाने पर भी विचार किया जायेगा।

कृषि निर्यात के लिए नॉन टेरिफ बेरियर्स समाप्त करने के विशेष प्रयास करे केन्द्र

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नीति आयोग की बैठक में संबोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए **नॉन टेरिफ बेरियर्स** हटाने पर भारत सरकार से विशेष प्रयास करने को कहा है। श्री नाथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नीति आयोग की कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि भारत से बाहर के देशों विशेषकर यूरोप और अमेरिका में कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में, जो अड़चनें हैं उन्हें दूर करने की बड़ी जरूरत है। इससे हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में संरचनागत सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि ई–नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को किसान हितैषी बनाने के लिए पूरे देश में कॉमन स्टेंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आने वाले सालों में कांट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदले हुए परिवेश में कांट्रेक्ट फार्मिंग को एक नया स्वरूप देने, प्रोत्साहित करने और आवश्यक सुविधाएँ देने की नीति बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई नीति में किसान और व्यापारी दोनों के हितों का संरक्षण हो।

मुख्यमंत्री ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। किसानों के व्यापक हित में यह जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने खाद्य प्र–संस्करण के क्षेत्र को नई संभावना वाला क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि इससे हम किसानों की आय में खासी वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ऐसी नीति बनानी होगी जो व्यापक होने के बजाए क्षेत्र विशेष आधारित है। मुख्यमंत्री ने हार्टिकल्चर और फ्लोरीकल्चर पर भी अधिक फोकस करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह भी एक क्षेत्र है जिससे हम किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि निश्चित ही उनके दिए गए सुझावों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और कृषकों की आय बढ़ेगी।

बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू उपस्थित थे।

सायबर सुरक्षा पर कार्यशालाओं का आयोजन

इन्दौर। सहकारिता क्षेत्र को सायबर अपराध, सुरक्षा उपाय व आई.टी. एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिये म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में सायबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा माह जुलाई 2019 में इन्दौर शहर की अपेक्स बैंक मुख्य शाखा विजय नगर, निहालपुरा शाखा व आनंद बाजार शाखा तथा नागरिक सहकारी बैंक मुख्यालय सुभाष मार्ग में एक दिवसीय निःशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सायबर अपराध के प्रकार, तरीके व उनसे बचाव की तकनीक तथा आई.टी. एक्ट के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यक्रम को उनके कार्यक्षैत्र के लिये बहुत उपयोगी बताया गया। अपेक्स बैंक के प्रबंधक श्री गणेश यादव तथा नागरिक सहकारी बैंक के प्रभारी अधिकारी व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री आनन्द खत्री द्वारा कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गुणवत्ता बढ़ाकर को-ऑपरेटिव क्षेत्र कार्पोरेट.....

उन्होंने कहा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति लाने में सहकारिता की भूमिका रही है।

श्री प्रदीप नीखरा प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक भोपाल ने मध्य प्रदेश के बैंकिंग क्षेत्र में संचालित योजनाएं जैसे ऋण माफी आदि पर प्रकाश डाला तथा श्री अरूण जोशी प्र. प्रचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल ने मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण की संचालित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास, अजीविका मिशन प्रशिक्षण, आनलाइन प्रशिक्षण पर प्रस्तुति दी। प्रदेश में संचालित योजनाओं की काफी सराहना हुई।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. के. पाटील ने बताया कि उनका विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान करने को तैयार है। सहकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उत्पादों के प्रसंस्करण का कार्य बेहतर तरीके से कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आई.सी.ए.आर. ने इस विश्वविद्यालय को देश के टॉप टेन विश्वविद्यालयों की रेंकिंग में स्थान दिया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सत्यनारायण शर्मा ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया और इसके लिए संस्थान प्रारंभ करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना को सहकारिता से जोड़ने पर लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उपाध्यक्ष डॉ. बृजेन्द्र सिंह मध्यप्रदेश से म. प्र. राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अरूण सिंह तोमर ग्वालियर, श्री प्रदीप नीखरा प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक भोपाल, श्री एस.के. जैन प्रचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव, श्री अरूण जोशी प्र. प्रचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल सहित बड़ी संख्या में सहकारिता से जुडे लोग उपस्थित थे।

जबलपुर में व्याख्याता श्री दिलीप मरमट को भावभीनी बिदाई

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में पदस्थ व्याख्याता श्री दिलीप मरमट को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर स्थानान्तरण होने पर केन्द्र की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। आयोजन में व्याख्याता श्री एस.के. चतुर्वेदी ने व्याख्याता श्री मरमट के प्रति हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त की और कहा कि उनका कार्यकाल केन्द्र जबलपुर में स्मरणीय रहा है। केन्द्र की ओर से प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार, श्री चेतन गुप्ता, लिपिक श्री एन.पी.दुबे, श्री पीयूष राय ने भी विचार व्यक्त करते हुए श्री मरमट के सक्रिय सहयोग की चर्चा की। प्रांरभ में केन्द्र स्टाफ की ओर से श्री मरमट का स्वागत करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। आयोजन के अन्त में व्याख्याता श्री दिलीप मरमट ने कार्यकाल को यादगार बताते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

म.प्र. के भविष्य निर्माण के लिए नई कार्य-संस्कृति, प्रशासनिक सुधार और सोच में परिवर्तन जरूरी

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किया ''आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश'' का विमोचन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश के भविष्य निर्माण के लिए नई कार्य–संस्कृति विकसित करने, प्रशासनिक सुधार करने और सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊँचाइयाँ हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश का नवनिर्माण करने में सरकार के सलाहकार बनें।

मुख्यमंत्री यहाँ एक राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा प्रकाशित **आइकन्स ऑफ मध्यप्रदेश** कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर रहे थे। इस बुक में ऐसी कई हस्तियों की उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्वों को शामिल किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शून्य से शिखर तक की यात्रा की और अब मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित हस्तियों को सम्मानित किया। जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के भविष्य निर्माण के संबंध में अपने विचार रखते हुए श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश को नई सोच की जरूरत है। नई निवेश और नई कृषि क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है । चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रौद्योगिकी का। कृषि का क्षेत्र हों या उद्योग का। परिवर्तनों के साथ चलते हुए अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा अन्यथा पीछे छूट जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो संस्थान परिवर्तन के साथ नहीं चले वे या तो पीछे छूट गये हैं या समाप्त हो गये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या सीखना है, इससे ज्यादा ध्यान अब हमें सीखने के तरीकों पर लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उद्योग क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की आवश्यकता है। निवेश की मांग नहीं की जा सकती। इसे सिर्फ प्रयासपूर्वक आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करने वाली और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने वाली हस्तियों का आभार जताते हुए आग्रह किया कि मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने में भी सरकार के साथ चलें।

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री आरिफ अकील ने किया पौध-रोपण

भोपाल। सामान्य प्रशासन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील और विभिन्न धर्मो के धर्मगुरुओं में यहाँ ईदगाह हिल्स पर पौध–रोपण किया। संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने भी पौध–रोपण किया।

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने भोपालवासियों से कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सब अपने घर–आंगन और शहर में पौधे लगाएं। पौधों के पेड़ बनने तक उनकी पूरी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाने में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

आँगनवाड़ी रजिस्टर पर गलत जानकारी पर होगी कड़ी कार्यवाही

मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। महिला–बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने निर्देश दिये हैं कि आँगनवाड़ी रजिस्टर में गलत जानकारी अंकित होने पर संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी आँगनवाड़ी के कार्यकर्ता और सहायियका पर कार्रवाई की जाये, जो रजिस्टर में संचालित बतायी जा रही है परन्तु यथार्थ में बंद है। श्रीमती इमरती देवी आज मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं।

श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि ऐसे चिन्हित जिलों, जहाँ अति कुपोषित बच्चे हैं, की लगातार मॉनीटरिंग संचालनालय स्तर पर भी सुनिश्चित की जाये। महिला–बाल विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनवाड़ियों में बच्चों को आकर्षित करने के लिये सिर्फ खाद्य पदार्थों पर निर्भर न रहें। अन्य गतिविधियों को भी सम्मिलित करें, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं और दूसरे शहरों से पढ़ने के लिये आयी छात्राओं आदि को रहने के लिये विभाग द्वारा संचालित वसति गृह की जानकारी विज्ञापन, पोस्टर, पेम्फलेट आदि के माध्यम से प्रचारित की जाये। श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि आँगनवाड़ियों में उदिता योजना में सेनेटरी नेपकिन की मशीनें लगाने के लिये उस क्षेत्र के उद्योगों से सीएसआर के अंतर्गत मदद लें।

सभी विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालय में ई–ऑफिस कार्य–प्रणाली क्रियान्वयन के निर्देश

भोपाल। राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों में त्वरित कार्यवाही के लिये ई–ऑफिस कार्य–प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कार्य–प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर क्रियान्वयन समिति गठित करने के लिये कहा है। सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स से कहा गया है कि सबसे पहले मास्टर्स ट्रेनर्स का चयन करें। सभी अधिकारियों–कर्मचारियों की ई–मेल आईडी बनवाएँ। मास्टर डेटा और फाईल हेड्स डेटा भी तय किए गए प्रारूप में उपलब्ध करवाएँ। ई–आफिस प्रशिक्षण भी आयोजित करें। जिलों के सूचना विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नस्तियों के डिजि– टाइजेशन तथा पुरानी नस्तियों के विनिष्टीकरण के निर्देश दिये गये हैं।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा पूरा करेगी सरकार - मुख्यमंत्री

वकीलों की हाउसिंग सोसायटी को मिलेंगी सभी सुविधाएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया था। सरकार इसे अवश्य पूरा करेगी। जल्दी ही कैबिनेट में इसे और ज्यादा सक्षम बनाने पर विचार कर अंतिम रूप दिया जायेगा। श्री कमल नाथ ने वकीलों की माँग के जवाब में कहा कि यदि वे अपनी हाउसिंग सोसायटी बनाते हैं, तो सरकार उन्हें सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री यहाँ मिंटो हाल में वकीलों की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। परिचर्चा से पहले सहभागियों ने दो मिनट मौन धारण कर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांगेस नेत्री दिवंगत श्रीमती शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वकीलों की सबसे बड़ी वैचारिक प्रतिबद्धता है संविधान और कानून की रक्षा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे अनूठा संविधान है। यह ऐसे देश का संविधान है, जहाँ विविधता है। यह जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति, परंपराओं की विविधताओं से भरापूरा देश है। ऐसे देश का संविधान आज पूरे विश्व के लिये उदाहरण है। इसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वकालत के पेशे से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पेशे का सम्मान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के कानून संविधान से ही जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, बराबरी और न्याय, प्रजातंत्र के निर्माणकारी तत्व हैं। इसके बावजूद स्वतंत्रता और बराबरी की सीमाएँ हैं लेकिन न्याय की कोई सीमा नहीं है। इसलिये वकालत के पेशे का सम्मान करने की जरूरत है।

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने वकीलों का स्वागत करते हुए कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन कानून के मसौदे पर सम्पूर्णता से विचार किया जा रहा है। इसमें वकीलों की सुरक्षा के हर मुद्दे को शामिल किया जा रहा है, जिससे यह आदर्श कानून बने। उन्होंने बताया कि वकीलों का बीमा और उन्हें पेंशन देने जैसे मुद्दों पर भी विचार चल रहा है। जल्दी ही ठोस परिणाम सामने आयेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हर वचन पूरा होगा।

राज्य सभा सदस्य श्री विवेक तन्खा ने एक्ट की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। एडवोकेट जनरल श्री शशांक शेखर एवं विभिन्न जिलों से आये सीनियर एडवोकेट उपस्थित थे।

जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषि सखियों का दल पंजाब पहुंचा

आजीविका समूह की दीदियां पंजाब में सिखायेंगी जैविक खेती के गुर

अनूपपुर। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कम लागत जैविक कृषि तकनीक विषय पर महिला स्व सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण एवं उनके खेतों में प्रदर्शन हेतु पंजाब के चार जिलों (गुरदासपुर, फिरोजपुर, संगरूर एवं पटियाला) में सीआरपी ड्राइव का संचालन किया जा रहा है, जिला अनूपपुर से चार सदस्यीय दल के रूप में कृषि सखी चम्पा सिंह, राधा सिंह, इंद्रवती राठौर एवं यशोदा धनवार पंजाब पहुंच चुकी हैं। सीआरपी ड्राइव के दौरान कृषि सखियों द्वारा जैविक कृषि को अपनाने एवं कम लागत जैविक कीटनाशक दवा एवं जैविक खाद निर्माण आदि पर ग्रामीण कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता हैस

सामान्यगतः गरीब परिवारों की यह महिलाएं जो कभी घर से बाहर निकलने एवं लोगों से बात करने तक का साहस नहीं कर पाती थीं, आज अपनी लगन एवं मेहनत से पंजाब जैसे राज्यस में जाकर वहां के स्व सहायता समूह की दीदियों को जैविक कृषि एवं कम लागत कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। जिला परियोजना प्रबंधक एसआरएलएम श्री शशांक प्रताप सिह ने बताया कि स्वव सहायता समूह से जुड़ने के बाद इन समूह सदस्योंस को कृषि सखी के रूप मे चिंहित कर विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान कर इनका क्षमतावर्धन किया गया एवं आज ये महिलाएं आजीविका मिशन के माध्यम से अपने घर से निकलकर अन्य राज्यों तक पहुँच बना ली हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है। पंजाब राज्य आजीविका मिशन के साथ हुए अनुबंध अंतर्गत यह दूसरी मास्टर कृषि सखी ड्राइव है जो कि 23 जुलाई से 06 अगस्त तक 15 दिवस हेतु संचालित रहेगी। जिले की कृषि सखी पूर्व में भी उत्तरप्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में महिला कृषकों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। ड्राइव संचालन हेतु सम्पूर्ण समन्वय आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक कृषि राजकुमार जाटव द्वारा किया जा रहा है।

पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से सस्ती और आसान हुई धान रोपाई

आगर–मालवा। जबलपुर जिले में पाटन विकासखंड के ग्राम करारी निवासी किसान अर्जुन पटेल अपने खेत में धान की रोपाई के लिये पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। मशीन से कम समय में अधिक रोपाई हो जाती है और मजदूरी की बचत भी होती है। मशीन की कीमत 14 लाख 50 हजार रुपये है, जिसमें कृषि अभियांत्रिकी विभाग 5 लाख सरकारी अनुदान भी दे रहा है।

जिला कलेक्टर ने किसान अर्जुन के खेत पर मशीन की उपयोगिता देखी। अर्जुन ने उन्हें बताया कि पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान की रोपाई में करीब एक हजार रुपये प्रति एकड़ लागत आती है। एक साथ 6 लाइन में एक दिन में 8 से 10 एकड़ तक आसानी से रोपाई होती है। पहले एक एकड़ में धान रोपाई पर करीब 4 हजार रुपये लागत आती थी और 15–20 मजदूरों की टोली एक दिन में एक एकड़ में ही बोनी कर पाती थी।

अर्जुन पटेल बताते हैं कि नई मशीन **राईट ऑन टाईप फोर व्हील** है। इसे एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है। मशीन काली मिट्टी में भी आसानी से रोपाई करती है, कीचड़ में नहीं धँसती। अब जिले के किसान बड़ी संख्या में इस मशीन का उपयोग करने लगे हैं।

मीठी तुलसी और कद्दू की खेती से कमलेश–देवांशी बने उन्नत किसान

भोपाल। कटनी जिले के प्रगतिशील युवा किसान कमलेश हल्दकार और देवांशी देवा ने उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को बेहतर आमदनी का जरिया बना लिया है। कमलेश हल्दकार ने ग्राम पंचायत इमलिया में 15 एकड़ में उन्नत किस्म के कद्दू व्हीएनआर–पी4 की बोनी की। अभी इनके खेत से प्रतिदिन 60–70 क्विंटल कद्दू उत्पादन हो रहा है। कमलेश इसे जिले की मण्डी के साथ राज्य के बाहर प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) की मण्डी में भी बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

युवा कृषक देवांशी देवा ग्राम मुंगेली में 30 एकड़ क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती कर रही हैं। देवांशी ने खेत में कॉन्टेक्ट फार्मिंग के माध्यम से स्टीविया (मीठी तुलसी) का पौधा–रोपण कराया है। औषधीय मीठी तुलसी का मदर प्लान्ट भी तैयार कर रही हैं। इससे जिले के अन्य किसानों को मीठी तुलसी के पौधे बेचेंगी।

उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ इन युवा किसानों को उत्कृष्ट कृषि के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही, ग्रामीणों को भी औषधीय पौधों की खेती के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अजा-अजजा, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण

भोपाल। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध–घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों को इस संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

अधिकारियों से कहा गया है कि जिस आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 1984) अथवा उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी होने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, उसे लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये विवश न किया जाये। राजस्व अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर अथवा शिविर में जाँच कर आवेदन–पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करें। इसके लिये आवेदक/ संबंधित सरपंच/ पार्षद/ ग्राम, मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करें। स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुशंसा करें। जनजातियों के ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के किसी सदस्य पिता/भाई/बहन को पूर्व में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, उन मामलों में छान–बीन नहीं करते हुए जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के निर्देश हैं।

मिलावटखोरों पर रासुका और जिला बदर की कार्यवाही होगी : श्री सिलावट

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने मिलावट की रोकथाम के लिये वीडियो कांफ्रेंस में दिये निर्देश

भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने कहा है कि दूध और दूध से बने पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बेखौफ होकर मिलावटखोर व्यापारियों पर कार्यवाही करें। आवश्यक होने पर रासुका और जिला बदर की कार्यवाही की जाए, जिससे लोग मिलावट करने से डरें। श्री सिलावट ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संरक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश में यह संदेश जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान प्रभावी रहा। श्री सिलावट मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री सुधि रजंन मोहन्ती की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट की बुराई को खत्म किया जाये, नहीं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिला मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखण्ड सहित सभी कस्बों में खाद्य सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाये। मिलावटी सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरूदध भी कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक सहित नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूदध सक्रिय रहने और परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें और दूध, मावा और दूध से बने अन्य पदार्थों तथा तेल के लगातार सेम्पल लिये जायें तथा कार्यवाही नामजद हो। मिलावट में लिप्त संस्थानों के मालिकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट देशद्रोह–राजद्रोह जैसा अपराध है। इसके विरूद्ध कार्यवाही भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने सतना, राजगढ़, बड़वानी, सागर, कटनी सहित अन्य जिलों से मिलावट के विरूदध की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कांफ्रेंस में जिला अधिकारियों से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिये जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित थे। कॉफ्रेंस में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स के साथ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी जिला एनआईसी केन्द्रों में उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्रम पेंशन योजना में आशाओं ने कराया पंजीयन

60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलेगी 3 हजार रु. प्रतिमाह पेंशन

सीहोर। असंगठित कामगारों के लिए संचालित प्रधानमंत्री श्रम पेंशन योजना में स्वास्थ्य विभाग की 610 आशा कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। योजना के अंतर्गत हितग्राही आशा कार्यकर्ता की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति उपरांत प्रतिमाह 3 हजार रूपए की पेंशन राशि प्राप्त होगी। योजना के लिए 18 से 40 वर्ष आयु की आशा कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगी पात्र है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम पेंशन योजना के अंतर्गत जिन आशा कार्यकताओं तथा आशा सहयोगी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष वर्ष तक हो तथा जिसकी मासिक आय 15 हजार रूपए से कम हो योजना के लिए पात्र हितग्राही है। योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का तथा 50 प्रतिशत अंशदान हितग्राही आशा कार्यकर्ता द्वारा जमा किया जाएगा। मासिक राशि हितग्राही आशा की आयु के आधार पर निर्धारित की गई है। अंशदान की राशि हितग्राही के बैंक खाते से प्रतिमाह स्वतः जमा होगी।

जिले में करीब 610 आशा कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है जिसमें आष्टा से 210 आशा कार्यकर्ता, बुदनी 90, इछावर 100 , नसरूल्लागंज 93,सीहोर शहरी क्षेत्र से 15 तथा श्यामपुर में 102 आशा कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन पेंशन योजना के लिए कराया है। जिले में 1133 आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगी आयु अनुसार योजना के लिए पात्र हितग्राही है। शेष आशाओं के पंजीयन की प्रक्रिया जारी हैं।

कृषकों के रेशम पालन हेतु ई–पंजीयन प्रारंभ

सीहोर। रेशम संचालनालय द्वारा प्रदेश के ऐसे कृषक जो निजी भूमि में 01 एकड़ क्षेत्र में शहतूती पौधरोपण एवं रेशम कृमिपालन कर ककून उत्पादन करना चाहते है, उसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था ई–रेशम पोर्टल www.eresham.mp.gov.in पर प्रारंभ की गई है । रेशम कृमि पालन में रूचि रखने वाले कृषक अपना आवेदन उक्त पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ई–रेशम पोर्टल में संपर्क कर सकते है।

स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित

छतरपुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं से स्वरोजगार स्थापना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। स्वरोजगार के इच्छुक युवक–युवती मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और आर्थिक कल्याण योजना के लाभ के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह योजना के तहत 10 महिलाओं के समूह को लाभांवित किया जाएगा।

समिति के सीईओ ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष क्रमांक 27 में संबंधितजन अपने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर परिचय पत्र के साथ सम्पर्क कर सकते हैं। ऋण के आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समिति के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान और खेत तालाब के नक्शे तथा स्वीकृति अब ऑनलाइन

भोपाल। राज्य शासन द्वारा सरपंचों की सुविधा की दृष्टि से "खेत तालाब" और ग्रामीण क्रीड़ांगन बनाने के लिए नक्शा और प्राक्कलन को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन कार्यो के लिए सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए प्रदेश में "सिक्यूर" साफ्टवेयर लागू किया गया है।

इसमें किसान भाइयों के खेतों में जल–सरंक्षण के लिए बनाए जाने वाले "खेत–तालाब" की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। खेत में 400 घन मीटर के तालाब निर्माण के लिए 38 हजार 680 रूपये, 1000 घनमीटर तालाब के लिए 1 लाख 294 रुपये तथा 3600 घनमीटर के तालाब के निर्माण के लिए 3 लाख 982 रूपये की स्वीकृति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीडांगन के निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। इसमें 100x100 मीटर के मैदान के लिए 4 लाख 4 हजार 610, 800x60 मीटर के मैदान के लिए 2 लाख 19 हजार 602 तथा 60x10 मीटर आकार के मैदान के लिए 1 लाख 34 हजार 369 रूपये की स्वीकृति दी जाएगी। इन सभी मैदानों के लिए आदर्श नक्शे भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये हैं।

अनूपपुर के किसान ज्ञान सिंह ने उद्यानिकी फसल से कमाए 4.50 लाख

भोपाल। प्रदेश में उद्यानिकी फसलें किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का सशक्त जरिया बन गई हैं। अनूपपुर जिले के किसान ज्ञान सिंह को इस वर्ष आम की खेती से लगभग 2 लाख 50 हजार और आँवले के पेड़ों से लगभग 2 लाख की अतिरिक्त आमदनी हुई है। इस तरह उन्होंने परम्परागत खेती के अलावा 4.50 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की है।

किसान ज्ञान सिंह को उद्यानिकी विभाग की फल क्षेत्र विस्तार योजना में आँवला के 800 और आम के 200 पौधे निःशुल्क मिले थे। इन्होंने पौधों को बड़ी मेहनत से पाला–पोसा। अब ये पौधे पेड़ बन गए हैं और फल दे रहे हैं। ज्ञान सिंह को उद्यानिकी अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन भी मिला है।

पत्रकार निडर तथा निष्पक्ष होकर प्रश्न पूछें और आलोचना भी करें

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किया पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए सत्र का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पत्रकारों से कहा है कि निष्पक्षता के साथ निडर होकर सरकार से प्रश्न पूछें और आलोचना भी करें। श्री नाथ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के ''उत्कृष्टता की ओर सत्रारंभ 2019'' का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने पेशे का सम्मान करें और इसकी शपथ भी लें।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि पत्रकारिता प्रलोभन और दबाव से दूर रहकर भारत के संविधान को आत्मसात करे, जो हमें विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सुविधा होती है, जब मैं अपनी सरकार की योजना और व्यवस्था की आलोचना अखबारों में पढ़ता हूँ। मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। इससे मुझे अपनी सरकार की कमियों को दूर करने में सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे नवागत छात्र–छात्राओं से कहा कि वे एक ऐसे पेशे से जुड़े हैं, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए निष्पक्ष होकर काम करें क्योंकि निर्भीक और निष्पक्ष लेखन प्रजातंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार और समाचार–पत्र सरकार के प्रकाशन नहीं हैं। आपको आलोचना करने का अधिकार है और यह आपका कर्त्तव्य भी है।

श्री कमल नाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा और ज्ञान के मूल अंतर को समझें। शिक्षा प्राप्त करने की सीमा है लेकिन ज्ञान जीवन पर्यन्त अर्जित करते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों से कहा कि वे अपनी शिक्षा पद्धति को आज के समय की पीढ़ी से जोड़ें। विश्व और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार हमारी शिक्षा हो, तभी हम अपनी भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि भारतीय संविधान पूरे विश्व में अनूठा है। कई देशों ने हमारे संविधान के निर्माता डॉ. अंबेडकर की सहायता से अपने देश का संविधान बनाया है। हमारा संविधान ऐसा है, जो अनेकता में एकता का संदेश देता है। यही विशेषता पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। जो देश बाँटने पर विश्वास करते हैं, वे कभी पनप नहीं पाते।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने विश्वविद्यालय के अध्ययन संस्थान में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और कर्मचारियों के बीमा में विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें सरकार पूरा सहयोग देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निकलने वाला हर विद्यार्थी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार बनकर अपने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने नए सत्र के सिलेबस का विमोचन किया। मुख्यमंत्री को शाल–श्रीफल और स्मृति–चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा स्वागत पुस्तक भेंट की गई।

विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दीपक तिवारी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की संकल्पना थी। उन्होंने 32 वर्ष पूर्व खंडवा में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में इसकी अभिव्यक्ति की थी। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय को संविधान की विचारधारा के अनुरूप उत्कृष्ट बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं। कई नवाचार के साथ सोशल मीडिया में फेक न्यूज का जो चलन बढ़ रहा है, उससे पत्रकारिता के विद्यार्थियों को सजग–सतर्क करने के लिए अलग से प्रोपेगेंडा विभाग स्थापित किया जा रहा है। यह विभाग उन्हें सोशल मीडिया की अज्ञानता और फेक न्यूज से सजग और सतर्क रहने के लिए शिक्षित करेगा।

सभी किसानों को जल संरक्षण के लिए आगे आकर सहभागिता करना चाहिए

एक दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर ने किया आव्हान

बुरहानपुर। सभी किसानों को जल का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। यह बात कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म के प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भूमिगत जलस्तर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए सभी किसानों एवं आदान विक्रेताओं से आव्हान किया कि भूमिगत जल स्तर बढाने के लिये पुराने बंद पड़े नलकूपों और कुओं को बरसात के जल से रिचार्ज तकनीकि जानकारी अपनाकर जलस्तर को बढाये। जलवायु परिवर्तन को देखते हुये हर खेत की मेढ पर पेड हर किसान को लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में पौधे पर्याप्त मात्रा में शासकीय नर्सरी में उपलब्ध है। साथ ही किसानों को सलाह दी गई कि खेती के अलावा बागवानी, पशुपालन एवं खेती आधारित छोटे–छोटे प्रसंस्करण उद्योग अपनाकर आय के स्त्रोत को बढ़ा सकते है। किसान मित्रों को से अनुरोध किया कि खेती की छोटी–छोटी तकनीकी जानकारी वैज्ञानिकों तथा विभाग के अधिकारीयों से सीखकर किसानों तक पहुंचाई जाये1

कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र बुरहानपुर के डॉ. भूपेन्द्रसिंह ने खरीफ की फसले, सोयाबीन, कपास तथा मक्का के उत्पादन के संबंध में तकनीकि सलाह एवं कपास में गुलाबी इल्ली के नियंत्रण के बारे में बताया। डॉ. कार्तिकेय सिंह द्वारा मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से किसानों से चर्चा की। फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिये थायमिथाझम 12.6 प्रतिशत एवं लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत की मात्रा 0.25 एम.एल. प्रति लीटर पानी या क्लोरेट्रानि–लिप्रोएल 18.5 प्रतिशत 0.4 मिली प्रति लीटर पानी या स्पाईनटोरम 11.7 प्रतिशत 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में किसी एक कीटनाषक का घोल बनाकर छिड़काव करें। उप संचालक कृषि श्री एम.एस. देवके ने किसानों, आदान विक्रेताओं तथा किसान मित्रों को संबोधित कर खरीफ फसलों के प्रबंधन एवं कीटों की रोकथाम हेतु चर्चा की। इस अवसर पर कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जापानी तकनीक से किया पौधारोपण

नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पीछे लगाए हजारों पौधें

खरगोन। नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पीछे की ओर सोमवार को जापान की मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया गया। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड के विशेष मार्गदर्शन में इस नवीन तकनीक के सहारे कलेक्टर भवन के आसपास वाले क्षेत्र में जंगल स्थापित करने के लिए यह पहल की गई है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री डाड ने त्रिवेणी भी रोपी। साथ ही वृक्षारोपण के लिए नगर पालिका, इन्नरवील क्लब और शहर के गणमान्य नागरिकों सहित पत्रकारों ने भी पौधारोपण में सक्रिय भूमिका निभाई। पौधारोपण में फल, फूल और छायादार पौधें लगाएँ गए। इनमें बादाम, पीपल, बरगद, शीशम, बांस, नीम, करंज आदि पौधे लगाए गए। पौधारोपण में समस्त जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष पंक्ति में लगाए पौधे

कलेक्टर भवन के पीछे किए गए पौधारोपण में तीन विशेष प्रकार की पंक्ति बनाई गई, जिसमें एक निश्चित आकार से गड्डे निश्चित गहराई में किए गए। पहली पंक्ति में एक हजार मीटर क्षेत्र के अलावा दो अन्य 500–500 मीटर वाले क्षेत्र चिन्हांकित किए गए, जहां पौधारोपण किया गया। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पौधे तीन गुना गति से वृद्धि करते है, जो निश्चित समय में जंगल का रूप लेता है। 5 वर्षों में जो जंगल बनता है, वह केवल 2 वर्षों में ही इस तकनीक से बन सकता है। कलेक्टर श्री डाड ने यह भी कहा कि यहां 25 हजार पौधे इसी पद्धति से लगाए जाएंगे। फिलहाल यहां 10 हजार पौधे लगाने की तैयारी कर ली गई है।

ऊर्जा संबंधी विषयों पर विचार के लिए मंत्रि–परिषद समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन ने ऊर्जा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार के लिये मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया है। समिति मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने वाले ऊर्जा से संबंधित चुनिंदा विषयों पर मंत्रि–परिषद को अपनी अनुशंसा देगी। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा समिति के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा समिति के सचिव होंगे।

समिति में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, वन मंत्री श्री उमंग सिंघार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल और वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत सदस्य होंगे।

सौर ऊर्जा से जगमग होगा खरगोन का कलेक्ट्रेट भवन

भोपाल। अब खरगोन जिला मुख्यालय पर नया कलेक्ट्रेट भवन भी सौर ऊर्जा से जगमग होगा। भवन में पंखे, एसी, कूलर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपी आदि सारे काम इसी ऊर्जा से होंगे। इस भवन में बिजली भी रहेगी, लेकिन उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही होगा।

नये कलेक्ट्रेट भवन में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये बिजली पर होने वाले खर्च को तो कम करेंगे, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी फायदेमंद होंगे।

भवन में प्रतिदिन 240 यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता के 60 किलोवॉट के सोलर पम्प लगाये गये हैं। करीब 40 लागत के इन सोलर पम्प से प्रतिमाह 7200 यूनिट बिजली की बचत होगी। इस तरह प्रतिमाह बिजली बिल में लगभग 50 हजार रूपये की बचत होगी।

रुफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तुरंत बनाने पर पहेडा के सरपंच व सचिव की कलेक्टर ने की प्रशंसा

मंदसौर। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को तुरंत में अमल में लाने पर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव पहेड़ा की सरपंच श्रीमती श्यामा बाई पाटीदार एवं सचिव श्री शंभूलाल बारीवाल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस गांव के सरपंच व सचिव द्वारा आदेश का तुरंत पालन किया गया। इनसे हर किसी व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इन्होंने अपने साथ पूरे गांव के लिए लाभकारी काम किया है। इसलिए इनकी तारीफ किया जाना लाजमी है।

कलेक्टर श्री पुष्प ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को भी सख्त निर्देश दिए कि, वे भी अपने–अपने क्षेत्र में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें। प्रत्येक शासकीय भवन में जुलाई–अगस्त माह में अनिवार्य रूप से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनवाएं।

महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाओं की सदस्यता सूची का प्रकाशन

देवास। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाएं विकासखंड टोंकखुर्द ने बताया कि म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेशानुसार म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला देवास से संबंद्ध विकासखण्ड टोंकखुर्द की महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाओं यथा की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालयध्कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला देवासध्जनपद पंचायत टोंकखुर्द के सूचना पटल पर 25 जुलाई 2019 को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी सदस्य को म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 49 (ग)(05) के अनुसार होने वाले निर्वाचन हेतु इस पर कोई आपत्ति है तो वह मय प्रमाण के सूची प्रकाशित होने के दिनांक 25 जुलाई 2019 से 02 अगस्त 2019 तक संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला देवास में लिखित में प्रस्तुत कर सकते हे। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण संस्था कार्यालय पर 03 अगस्त 2019 को 11.00 बजे से किया जाकर सदस्य सूची का अंतिम मतदाता–सदस्यता सूची के रूप में प्रकाशित किया जावेगा।आपत्ति के निराकरण के दिन सदस्य स्वयं उपस्थित हो सकते है, आपत्ति के संबंध में प्रथक से व्यक्तिशः सूचना नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा सोच बदले-जीवन बदले पुस्तक का विमोचन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने विधानसभा में रवि सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक **सोच बदलें–जीवन बदलें** का विमोचन किया। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव तथा मीडिया प्रभारी श्रीमती शोभा ओझा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने विषय–वस्तु की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को सही दिशा देने और उन्हें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने में यह पुस्तक मदद करेगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनिल शास्त्री ने कहा कि पुस्तक युवा पीढ़ी की नकारात्मक सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सहायक होगी।

पुस्तक के लेखक श्री रवि सक्सेना ने बताया कि आज युवा पीढ़ी में आ रहे भटकाव और निराशा को रोकने एवं उन्हें रचनात्मकता से जोड़ने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया है। इस मौके पर डॉ. मीना सक्सेना, श्री नरेन्द्र सलूजा, श्री अमिताभ बाजपेयी, श्री आर.पी. सिंह, श्री संदीप वासवानी, श्री दुर्गेश शर्मा, श्री के.के. सक्सेना, श्री मुदित शास्त्री उपस्थित थे।

बैंकर्स के कार्यशाला संपन्न

खरगोन। आजीविका मिशन तथा नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में बैंकर्स संवेदीकरण/समूह बैंक लिंकेज की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 19 बैंकों के 53 ब्रांच मैनेजर उपस्थित हुए। जिला पंचायत सीईओ श्री डीएस रणदा ने कार्यशाला में कहा कि आजीविका मिशन सभी बैंकर्स को मिशन के कार्यो में मदद करें। बैंकर्स को कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में सीसीबी बैंक के प्रबंधक श्री मुकेश बार्चे, आजीविका मिशन की डीपीएम सीमा निगवाल, आरसेटी निदेशक श्री धुर्वे उपस्थित रहे।

संस्कृति विभाग द्वारा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़। प्रदेश में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही पंजीकृत संस्थाओं से वर्ष 2019 –20 में अनुदान प्राप्त करने के लिए 14 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त संस्कृति संचालनालय के कार्यालय में जमा करवाए जा सकेंगे।

डेंगू एवं चिकुनगुनिया रोग से बचाव हेतु सावधानियां जरूरी

सीहोर। मच्छर जनित रोगों के उपचार से बेहतर है कि हम थोड़ी सी सजगता एवं सावधानियां रखकर ऐसी स्थिति बनाये, जिससे मच्छर पैदा ही नहीं होने पाये। इसके लिए आमजनों सहित अधिकारियों–कर्मचारियों को भी समुचित जानकारी होना अत्यंत जरूरी है जिससे आमजनों को भी इसके बारे में सही–सही जानकारी दे सकें।

डेंगु एवं चिकुनगुनिया का वाहक मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। नागरिकगण वर्षा के पानी को जमा न होने दें। आस–पास सफाई रखें और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचें। डेंगू के लक्षण में तेज बुखार, ऑखों, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना, शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू हो सकता है। चिकुलगुनिया के लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि हैं।

लक्षण पाये जाने पर खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकुनगुन्या पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा उपचार लें। बचाव के लिए पानी के बर्तन ढंक कर रखें। अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें। दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं। हैण्डपंप के आस–पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमे पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। आस–पास सफाई रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरी अस्तीन के कपड़े पहने और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचें। डेगू एवं चिकुनगुनिया की जॉच व उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।

काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए समिति पुनर्गठित

भोपाल। राज्य शासन ने काष्ठ आधारित उदयोगों की राज्य–स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समिति में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), संचालक/अपर संचालक उद्योग, प्रबंध संचालक संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, प्रबंध संचालक वन विकास निगम और मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विपणन) सदस्य होंगे।

नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का व्यावसायिक संचालन मार्च के अंत तक शुरू करवाने की रणनीति पर काम करें

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने की फूड पार्क की स्थिति की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभागों को मार्च के अंत तक नई खादय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के नये लक्ष्य तय कर उनका व्यावसायिक संचालन शुरू करवाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। वे यहां प्रदेश में फूड पार्क की वर्तमान स्थिति और खादय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की अनंत संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि फूड पार्क में सिर्फ प्लाट आवंटन और थोड़े से अधोसंरचनात्मक सहयोग से प्रगति का आकलन ठीक नहीं है। इकाईयों की सफलता उनके व्यावसायिक उत्पादन और उनके उत्पादों की बिक्री से तय होनी चाहिए। अधोसंरचना उपलब्ध कराना सिर्फ प्रारंभिक काम है।

वर्तमान में प्रभावी खादय प्रसंस्करण नीति 2014 के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति से ज्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति। कई राज्य बिना किसी खाद्य प्रसंस्करण नीति के भी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि छिन्दवाड़ा में आर्किड पार्क और मंदसौर में लहसुन, गुना में धनिया प्रसंस्करण पार्क, क्लस्टर या अन्य स्थानों पर किसी और प्रसंस्करण इकाईयों की संभावना बनती है तो तत्काल कार्यवाही करें। जो निवेशक या उद्यमी प्रदेश में अपनी रूचि दिखाते हैं उन्हें तत्काल सहयोग दें। उन्होंने छिन्दवाड़ा में आर्किड पार्क के लिए सात दिन में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि डाबर कंपनी ने आयुर्वेद औषधि पार्क के लिए मध्यप्रदेश को चुना है।

बैठक में कृषि मंत्री श्री सचिव यादव एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री अशोक सिंह द्वारा अपेक्स बैंक के प्रशासक का कार्यभार ग्रहण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) में नवनियुक्त प्रशासक श्री अशोक सिंह ने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर स्थित **सुभाष यादव भवन** में कार्यभार ग्रहण किया। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने उन्हें अपेक्स बैंक के प्रशासक का जो दायित्व सौंपा है, उस पर वे खरे उतरेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री का आभार व्यक्त किया।

सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि लम्बे समय बाद अपेक्स बैंक को कुशल नेतृत्व मिला है। श्री सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा तथा कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा कि श्री अशोक सिंह एक कुशल सहकारी नेता हैं, जिनके नेतृत्व में पुनरू अपेक्स बैंक एवं इससे संबद्ध सभी सहकारी संस्थाएँ प्रगति करेंगी।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री श्री अजय सिंह, पूर्व वाणिज्यिक कर मंत्री एवं अपेक्स बैंक के संचालक श्री भगवान सिंह, पूर्व सांसद श्री रामेश्वर नीखरा ने भी श्री सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। प्रारंभ में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा ने नवनियुक्त प्रशासक एवं अतिथियों का स्वागत किया।

एक लाख 97 हजार 612 रूपए का फसल ऋण माफ होने से खुश है किसान कन्हैया लाल

रायसेन। खेती–बाड़ी के लिए बैंक से लिया कर्ज चुका नहीं पाने के कारण कर्ज के बोझ से दबे जा रहे थे। हर वक्त कर्ज चुकाने की चिंता लगी रहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत मेरा एक लाख 97 हजार 612 रूपए का फसल ऋण माफ कर मेरे सीने से कर्ज जैसा बड़ा बोझ हटा दिया है। यह कहना है रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम पड़रियाखुर्द निवासी किसान श्री कन्हैया लाल का। किसान श्री कन्हैया लाल ने बताया कि उन पर सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक से खेती के लिए लिया गया एक लाख 97 हजार 612 रूपए का ऋण बकाया था।

राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वाधान में

मुर्गीपालन सहकारी समितियों हेतु महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल मे राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से मुर्गीपालन सहकारी समितियों हेतु महिला नेतृत्व विकास पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण मे मुर्गीपालन सहकारी समिति केसला, डिण्डौरी तथा देवरी की संचालको एवं सदस्यों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण में अतिथि व्याख्याता के रूप में सुश्री सृष्टि उमेरकर, डायरेक्टर शरण वेलकेयर फाउडेशन उद्यमिता विकास ने नेतृत्व विकास, डॉ भगवान मगनानी मुर्गीपालन से संबंधित प्रावधान तथा शासन से संबंधित विभिन्न योजनाओं, श्री श्री कुमार जोशी सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त ने सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं एवं सहकारी अंकेक्षण से सबंधित विभिन्न प्रावधान तथा श्री पृथ्वीराज सिन्हा, उप संचालक केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने समय प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। राज्य संघ की ओर से श्री संजय कुमार सिंह, ओ.एस.डी., श्री ए.के. जोशी, प्रभारी प्राचार्य, श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर प्रशिक्षक तथा श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षणार्थियों को श्री ए.के. जोशी, प्र. प्राचार्य एवं श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक के नेतृत्व में शासकीय कुक्कुट अनुसंधान प्रक्षेत्र, हताईखेड़ा भोपाल का अध्ययन भ्रमण भी कराया गया। अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रक्षेत्र के डॉ. संगीता तिवारी एवं डॉ. भार्गव एवं श्री शुक्ला ने प्रशिक्षणार्थियों को मुर्गीपालन से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा मुर्गीपालन से संबंधित विभिन्न सावधानियों से अवगत कराया। सत्र समन्वयक श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता थी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुर्गीपालन उत्पादक कंपनी भोपाल का उल्लेखनीय सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।